SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, it is a larger issue. The recommendations are very clear. In order to see that these recommendations are accepted, was there a wider discussion within the Government about these recommendations made by the CII, in order to increase production as also to take care of other issues mentioned in that?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, within the Agriculture Ministry the discussion is over. We are going to have discussions with the Planning Commission, Sir, the financial responsibility is on the higher side, but the recommendations are very useful. Water is a scarce commodity in this country and we have to give good weightage for it. We are going to, very effectively, take it up with the Planning Commission.

Study regarding problems of farming sector

*66. SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have carried out any authentic study of the problem afflicting the farming sector in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether Government are aware of the major bottlenecks impeding the growth in the agricultural sector; and

(d) if so, the steps proposed to be taken to remove them?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. A study entitled "State of Indian Farmers—A Millennnium Study" has been undertaken with focus on problems facing farmers like declining size of holdings, degradation of soil and water resources, and inadequate institutional credit support.

(b) The Study consists of two phases. Phase I pertains to preparation of papers by experts on the 25 identified subjects relating to agriculture, which contain a retrospective analysis of the Agricultural Development experience in post independence era. All the papers have been prepared, and are under printing. Phase II relates to Situation Assessment Survey (SAS) on Conditions of Indian Farmers. The National Sample Survey

Organisation (NSSO) has been entrusted with the SAS. The fieldwork for the survey was conducted as part of their 59th round with agricultural year 2002-03 (July-June) as the reference period. The Report on the survey is expected in 2005.

(c) The major bottlenecks impeding the growth in the agricultural sector are inadequate flow of credit, high debt burden and rates of interest, low size of operational holdings, dependence on rain for water in about 60 per cent of the net sown area, low productivity across States/regions and crops, and distortions in markets owing to inability of producers/farmers to directly sell their produce, etc.

(d) In order to extend much needed help and relief to the farmers, the Government has identified thrust areas for focused and priority attention, which include doubling of rural credit in three years, easing the burden to debt and high interest rate, market/price support to farmers for ensuring fair and remunerative prices, insurance of crops against production loss arising from natural calamities, creation of additional irrigation facilities and assistance to farmers under various agricultural, including horticultural, crop production programmes and market reforms.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, my first supplementary relates to part (c) of the reply laid on the Table. I would just like to know from the hon. Agriculture Minister whether disproportionate diversification and enthusiastic encouragement with those for the SAS may improve the production of certain hi-tech horticultural or some other export items of agriculture, at the cost of foodgrains of ours. So, I would like to know whether there is a chance that after some time, after some years, we may lose our self-reliance in so far as food security is concerned. Would the Minister be kind enough to reply to this anxiety of mine?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): सभापति महोदय, कृषि ऋण के प्रवाह को तीन वर्षों में दुगुना करने के लिए दिनांक 18.6.2004 को वित्त मंत्री जी ने ऋणग्रस्तता की समस्या के कारण विपत्ति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया है। उसमें कृषि ऋण का कुल प्रवाह जो 2003-04 में 80,000 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसे 2004-05 में बढ़ाकर लगभग 105,000 करोड़ रुपए किया जाएगा जो गत वर्ष की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक है। वाणिज्यिक बैंक वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण शाखा में औसतन कम से कम 100 नए किसानों को अपने दायरे में लाने का सरकार प्रयास कर रही है जिससे 50 लाख किसानों को उसका फायदा मिलेगा। डायवर्सिफिकेशन एक रणनीति के तहत

किसानों के अधिकाधिक हित में किया जा रहा है और देश में आत्मनिर्भरता पर कतई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अर्धा-शहरी शाखा बागवानी, मात्स्यिकी, जैव-खेती, कृषि प्रसंस्करण, पशुधन, सूक्ष्म छिड़काव के लिए भी माननीय सभापति महोदय ... (**व्यवधान**)... तालाब विकास और अन्य कृषि कार्यकलापों के लिए ...(**व्यवधान**)... कम से कम दो ...(**व्यवधान**)... उपाय लाने की बात ...(**व्यवधान**)...

श्री मनोज भट्टाचार्य: सभापति जी, मेरा सप्लीमेंट्री इससे बिल्कुल संबंधित नहीं था। मेरा सप्लीमेंट्री बिल्कुल सीधा था कि क्या आप सोचते हैं या मेरी यह एंग्जाइटी है कि डाइवर्सिफिकेशन पर जो ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जहां हाईटेक होर्टिकल्चर आइटम्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ेगी, फूल-पौधे बढ़ेंगे, वह एक्सपोर्ट होंगे, लेकिन इसके लिए जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज होंगे, क्या उससे जमीन की फर्टिलिटी में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? इसके लिए हमारे देश की फूड सिक्योरिटी जियोपर्डाइज होगी कि नहीं? मैंने ग्रीन कवर अभी नहीं पूछा, बाद में पूछूंगा, क्या मंत्री जी कृपा करके इसका जवाब देंगे?

श्री शरद पवार: जब डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई है तो इस बारे में सोचा गया है कि फूड सिक्योरिटी की कांसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन का प्रोग्राम लिया है। जहां तक होर्टिकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करने की बात आई है तो वहां ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात तय की है।

श्री मनोज भट्टाचार्य: सभापति जी, मेरा सप्लीमेंट्री ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बस हो गया।

श्री मनोज भट्टाचार्य: सभापति, मैंने एक सप्लीमेंट्री पूछा है, उसका ट्रांसलेशन Sir, I had to translate it in Hindi.

श्री सभापति: आपने दो सप्लीमेंट्री पूछे हैं, इससे ज्यादा नहीं ...(**व्यवधान**)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, it is a very important question. ...*(Interruptions)*... मैंने एक ही पूछा है सभापति जी ...(**व्यवधान**)... Sir, what is this? ...*(Interruptions)*... I do not understand this ...(*Interruptions*)... सभापति जी, मैंने एक ही पूछा है ...(**व्यवधान**)... Sir, what is this?

श्री सभापति: अच्छा पूछिए।

श्री मनोज भट्टाचार्य: सभापति जी, मेरा एक सवाल है, जो ऋण के बारे में है। वह यह है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड है Whether it seems to have been turned

into an easier route for meeting priority sector's lending operations, and as a result of the same, whether the farmers are suffering in terms of lower access to credit in general and the growth rate of credit for small and marginal farmers has declined substantially as compared to eighties. If so, what is the remedial measure that the hon. Minister is contemplating?

SHRI SHARAD PAWAR: One of the shortfalls, which the Indian farmer is facing, is limited availability of credit. There are at least 40 per cent farmers who are not eligible to get credit either because their being defaulters or because of various other reasons. That is the reason the Finance Minister yesterday made a major change. In three years' time agricultural credit will doubled in entire country. And this year alone Rs. 25,000 crores will be additionally provided, and those who are defaulters for them some new scheme will be introduced.

श्री राजनाथ सिंह: सभापति जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर का संदर्भ लेते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि फार्मर हो अथवा फूड प्रोसेसर हो, वह चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की उसे उचित कीमत मिले, संभवत: इसीलिए हर राज्य से ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट को अमेंड करने का आग्रह किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में अभी तक कितने राज्यों ने ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट में अमेंड किया है और किन-किन राज्यों ने किया है? साथ ही साथ सी॰आई॰आई॰ का यह भी कहना था कि राज्यों को मंडी टैक्स समाप्त करना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: सी॰आई॰ए॰?

श्री राजनाथ सिंह: नहीं, नहीं सी॰आई॰आई॰।

श्री सभापति: आपको सी॰आई॰ए॰ सुन गया? यह सुन लिया क्या?

श्री राजनाथ सिंह: अमर सिंह जी कभी-कभी कुछ ऊंचा सुन जाते हैं।

श्री अमर सिंह: हमारे बड़े भाई हैं, मैंने संशोधन किया है।

श्री सभापति: अच्छा ठीक है।

श्री राजनाथ सिंह: दूसरा प्रश्न यह है कि किन-किन राज्यों ने अब तो मंडी टैक्स समाप्त किया है? क्या ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट के अनुरूप अपने-अपने राज्यों में अमेंडमेंट करने में कुछ राज्यों ने अपनी व्यावहारिक कठिनाइयां सरकार के सामने रखी हैं? यदि रखी हैं तो वे कठिनाइयां क्या हैं?

श्री शरद पवार: मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका सवाल नेक्स्ट है? आपका अगला सवाल है। आपने जो पूछा वह यह सवाल नहीं है।

श्री सभापति: ठीक है, आगे दे दीजिए।